

non IATA general sales agents (GSAs) with administrative and financial links with IATA-approved travel agencies; and

(b) if so, its impact on Air-India's traffic earning potential and business both in India and abroad?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI A. P. SHARMA): (a) At the third Passenger Agency Conference (PAC) held in May, 1982 IATA members agreed to reintroduce the financial Link Clause in Resolution 876 in so far as IATA Area 3 is concerned. (This area primarily includes all the countries in the Middle East, Pakistan, India, South East Asian Countries, Japan and Australia.) The reintroduction of this clause would prohibit members from appointing non-IATA General Sales Agents (GSAs) who have administrative and financial links with IATA agents.

(b) This would enable Air India and other carriers in Area 3 to receive support from all IATA agents and no IATA agent would support a particular carrier to the detriment of Air India.

भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद में टकसाल मशीनों का बंकार पड़ा रहना

1372. **भीमती कृष्णा साही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि 4 लाख और 25 हजार रुपए की लागत की टकसाल मशीनें जिनका 1973 में आयात किया गया था, भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद में बंकार पड़ी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इससे खजाने को कितनी हानि हुई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार टकसाल हैदराबाद द्वारा जुलाई, 1972 में विदेशी संभरक

को दिए गए दो सिक्का निर्माण प्रेसों के आर्डर में से एक मशीन क्षतिग्रस्त स्थिति में जनवरी, 1974 में प्राप्त हुई और प्रेस के कुछ हिस्से भी गायब थे । जब इसे रेल द्वारा बम्बई से हैदराबाद तक ले आया जा रहा था तब यह प्रेस क्षतिग्रस्त हुई और इसके हिस्से गुम हुए क्षतिग्रस्त हिस्सों की लागत का ब्यौरा प्रेस के विदेशी संभरक के भारतीय एजेंट से अप्रैल 1978 में ही प्राप्त हो सका था । देशीय दृष्टिकोण से, हिस्सों का आयात करने के लिए महानिदेशक तकनीकी विकास की अनुमति प्राप्त करने के लिए जुलाई 1978 में ही कार्रवाई शुरू की गई और यह अनुमति सितंबर, 1979 में प्राप्त हुई । विदेशी मुद्रा जारी करने का प्रस्ताव मई, 1980 में किया गया । तथापि यह विस्तार करते हुए कि हिस्सों और मरम्मत के खर्च की लागत, मशीन की मूल लागत की तुलना में कहीं अधिक अर्थात् 4 लाख रुपए होने की संभावना है और यह कि उस समय हैदराबाद टकसाल को बन्द करने के फैसले के कारण कुछ अन्य प्रेसों के भी फालतू हो जाने की संभावना है, यह निश्चय किया गया कि उपर्युक्त प्रेस की मरम्मत करने के लिए हिस्सों का आयात करने के प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई न की जाए । इसकी बजाए इसे बम्बई टकसाल में (जहाँ यह मार्च, 1981 को स्थानांतरित की गई थी) इसलिए रखा गया कि इसके उपलब्ध हिस्सों को इसी प्रकार की अन्य सिक्का निर्माण प्रेसों की मरम्मत के लिए जब भी आवश्यकता हो, इस्तेमाल में लाया जाए । क्योंकि सरकार ने अब (फरवरी, 1982 में) हैदराबाद टकसाल का प्रचालन जारी रखने का फैसला किया है, मशीन को फिर से हैदराबाद में मरम्मत किए जाने के लिए स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) वाणिज्य लेखापरीक्षक की गणनाओं के अनुसार, प्रेस की पूंजीगत लागत के प्रयोग में न आने से इस संबंध में 1974—1981 की अवधि में ब्याज के रूप में लगभग 1.61 लाख रुपए की हानि होगी जिसका हिसाब सरकार की उधार लेने की दर पर लगाया गया है ।